जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 16 संख्याः 229 प्रभात हिण्डौन सिटी, रविवार 23 जून, 2024 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

सिर्फ इंसान ही ऐसे नहीं हैं जो दूध में भीगी रोटी या चाय में बिस्कुट डुबाकर खाना पसंद करते हैं, कुछ कॉकटू (काकातुआ) भी खाने से पहले अपने भोजन को गीला करते हैं। युनिवर्सिटी ऑफ विएना के शोधकर्ताओं ने पहली बार देखा कि, गॉफिन्स कॉकटू अपना भोजन पानी में डूबोकर खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग चाय में बिस्कुट डुबाते हैं। शोधकर्ताओं ने बायॉलजी जर्नल में लिखा है कि, किस तरह से उन्होंने पक्षीशाला में पक्षियों के कटोरों में रस्क, सूखे फलों के टुकड़े और पक्षियों के भोजन के पैलैट्स रखे, वहाँ पास में पानी भरे टब भी रखे हुए थे। बारह दिन चली रिसर्च में टीम ने रिकॉर्ड किया कि, पक्षियों ने अपना खाना पानी में डुबोया, क्या डुबोया, कितनी देर तक डुबोए रखा, और क्या फिर वो खाना खाया। टीम ने पाया कि, 18 में से 7 कॉकटू ने कम से कम एक बार तो अपना भोजन अवश्य गीला किया और दो पक्षियों ने तो हर बार रस्क को पानी में भिगोकर ही खाया। भिगोए जाने वाले भोजन में रस्क सबसे आम था। कभी-कभी इन पक्षियों ने बनाना चिप्स तथा सूखे नारियल चिप्स को भी पानी में डुबोया। टीम ने बताया कि, पक्षियों का यह विशिष्ट व्यवहार रस्क के प्रति अधिक था, जो कड़ा होता है, पर जल्दी से पानी सोख लेता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि, सातों कॉकटू ने भोजन कितनी देर तक डुबोया, इस अवधि में अंतर था। कुछ ने तो काफी देर तक रस्क पानी में डुबोए रखा। शोधकर्ताओं ने कहा, पक्षियों ने रस्क को इसलिए डुबोया क्योंकि, शायद वे इसे नर्म करना चाहते थे, इस व्यवहार से लगता है कि, वे भोजन तैयार करने के बारे में जानते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि, इस प्रक्रिया में, भोजन खाने की लालसा पर नियंत्रण रखने की ज़रुरत होती है, क्योंकि संतुष्टि मिलने में देर होती है, इसलिए पक्षियों का यह व्यवहार, भोजन के संदर्भ में उनकी चतुरता को दर्शाता है। शोध में बताया गया कि, चूँकि भोजन डुबोकर खाने की यह प्रवृत्ति जंगलों के इनके प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, इसलिए हमें लगता है कि, यह तत्क्षण ही किया गया "इनोवेशन" हो सकता है।

इंडिया गठबंधन प्रो-टैम स्पीकर की सहायतार्थ गठित पैनल में अपने सांसद नहीं भेजेगा?

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, प्रो-टैम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब की मदद के लिए गठित सांसदों के पैनल में इण्डिया गठबंधन से कांग्रेस सांसद के. सुरेश, टी.एम.सी. के सुदीप बंदोपाध्याय व डी.एम.के. सांसद टी.आर. बालू को मनोनीत किया है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जून। इंडिया ब्लॉक से तीन विपक्षी नेताओं को अध्यक्ष के पैनल के लिए नामित किया गया था जो प्रो-टैम स्पीकर भर्तृहरि महताब को सहयोग करने वाले थे। इन सूत्रों के हवाले से खबर है कि विपक्षी सांसद पैनल से अपना नाम वापस लेने वाले हैं।

यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि विपक्षी दलों को प्रो-टैम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब की नियुक्ति पर आपत्ति की है।

महताब, उड़ीसा की कटक सीट से भाजपा के सदस्य हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 91(1) के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रो-टैम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया है, वे 26 जून को लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष चुने जाने तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। विशेष संसद सत्र के दौरान प्रो-टैम स्पीकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराएंगे, इस दौरान उनके सहयोग के लिए अध्यक्षों के एक पैनल की भी घोषणा की जाएगी।

विपक्षी दलों के सूत्रों से खबर है कि विपक्षी दलों से तीन सांसद- कांग्रेस नेता के. सुरेश, टी.एम.सी. सांसद सुदीप बंदोपाध्याय तथा डी.एम.के. नेता टी.आर.बालू- का नाम प्रो-टैम स्पीकर को सहयोग करने वाले पैनल में रखा गया था, अब वे इस पैनल से हटने पर विचार कर रह हैं।

इस पैनल में भाजपा से लोकसभा सदस्य राधा मोहन सिंह व फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल सदस्य हैं।

कांग्रेस के अनेक नेताओं ने प्रो-टैम स्पीकर पद पर महताब की नियुक्ति को लेकर आपत्तियां प्रकट की है क्योंकि कांग्रेस के सांसद के. सुरेश का सदन में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इंडिया गठबंधन के ये तीनों सांसद पैनल की सदस्यता स्वीकार करेंगे।
- इंडिया गठबंधन का कहना है कि, कांग्रेस के केरल से सांसद के. सुरेश आठ बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। अतः सुरेश को प्रो-टैम स्पीकर न बनाकर ओडिशा से भाजपा के सांसद भर्तृहरि, जो सात बार ही सांसद बने हैं, को प्रो-टैम स्पीकर बनाना परम्परा का उल्लंघन है।
- अतः उल्लंघन के विरोध में, इंडिया गठबंधन प्रो-टैम स्पीकर की मदद के लिये गठित वरिष्ठ सांसदों के पैनल की सदस्यता अस्वीकार कर रहा है।
- संसदीय मामलों के मंत्री रिजीजू ने सरकार को सही बताते हुए कहा कि, सुरेश आठ बार तो सांसद निर्वाचित हुए हैं, पर, वे लगातार सांसद नहीं रहे हैं। वे 1998 से 2004 के बीच चुनाव हारने के कारण, सांसद निर्वाचित नहीं हुए थे।

क्या टी.एम.सी. व कांग्रेस में "अब्बा" हो गयी?

टी.एम.सी. नेता ममता बनर्जी ने, कांग्रेस पार्टी की वायनाड से प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अपनी सहमति दी

-श्रनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जून। आगामी संसद सत्र से पहले कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस ने अपने आपसी मतभेदों का समाधान कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के इस सुझाव को मान लिया है कि वे वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए चुनाव प्रचार करेंगी।

लोकसभा चुनावों के चरणबद्ध चुनाव प्रचार अभियान के दौरान और उसके बाद दोनों पार्टियां वस्तुत आपसी खींचतान में उलझी हुई थी और अधीर रंजन चौधरी कई बार तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ निशाना साध चुके थे। चुनावी प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी कोई तालमेल नजर नहीं आया था। चुनावों के परिणाम के बाद टी.एम.सी. में दूसरे नम्बर के पदाधिकारी अभिषेक बनर्जी विभिन्न मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के सदस्यों के साथ सक्रियता से मेलमिलाप करते देखे गए थे। परन्तु कांग्रेस के साथ नहीं। परिणामों के बाद बनर्जी सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मिले उसके बाद उन्होंने आप पार्टी के नेता राघव चड्ढा से मुलाकात की।

उसके बाद अभिषेक मुम्बई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने गए। इस सप्ताह के प्रारंभ में, टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें कल्याण बनर्जी, सागरिका घोष व साकेत गोखले शामिल थे, ने एग्जिट पोल पर स्टॉक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी. चिदम्बरम् कोलकाता जाकर, मु.मंत्री ममता बनर्जी से उनके ऑफिस में मिले, तथा प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने का आग्रह किया। ममता बनर्जी ने उनका सुझाव स्वीकार करते हुए अपनी सहमति दी।
- यह घटनाक्रम चौंकाने वाला इसलिए है, क्योंकि, लोकसभा चुनाव के दौरान ही नहीं, वरन, मतदान के बाद भी दोनों पार्टियों में तलवार खिचीं हुई थीं।
- टी.एम.सी. के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी सपा के अखिलेश यादव व आप के राघव चड्ढा से मुलाकात करके, इंडिया गठबंधन में अपना ग्रुप बनाने की चेष्टा की थी, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी।
- इसके बाद टी.एम.सी. का प्रतिनिधि मण्डल, मुम्बई जाकर शरद पवार से मिला, और एग्ज़िट पोल के मार्फत स्टॉक एक्सचेंज में हेराफेरी व घोटाले की जांच के लिए, मुम्बई में प्रदर्शन आयोजित किया।
- पर, प्रदर्शन में कांग्रेस आमंत्रित नहीं थी, हालांकि, राहुल गांधी ने सबसे पहले इस मुद्दे पर जे.पी.सी. गठित करने की मांग उठायी थी।
- "अब्बा" होने का सुबूत यह भी है कि, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहना शुरु किया कि, उनकी ममता बनर्जी से लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, तथा उन्होंने 2011 में सोनिया गांधी को राय दी थी कि, मार्क्सवादी पार्टी से लड़ने के लिये ममता बनर्जी से गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ही एक मात्र विश्वसनीय चेहरा हैं, बंगाल में।

भाजपा ने तमिलनाडू के मु.मंत्री से इस्तीफा मांगा

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जून। तमिलनाडू सरकार अवैध शराब दुखान्तिका को लेकर दबाव में है और विपक्षी दल अन्नाद्रमुक तथा भाजपा के प्रहार झेल रही है। तमिलनाडू के कल्लाकुरिची जिले के करूणापुरम में जहरीली शराब का सेवन करने के बाद अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है।

शराब दुखान्तिका के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी बनने की जद्दोजहद भी शुरु हो चुकी है और अन्नाद्रमुक ने इस मामले में बाजी मारते हुए इस प्रकरण को विधानसभा के भीतर और बाहर सड़कों पर बड़े सशक्त तरीके से उठाते हुए राज्य के मद्यनिषेध एवं आबकारी मंत्री एस. मुथुस्वामी के इस्तीफे की मांग की। भाजपा ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भाजपा का कहना है कि, तमिलनाडू में हुई शराब दुखांतिका में 55 लोग मारे जा चुके हैं और इसकी नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री स्टालिन की है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक अमेरिकी कंपनी से अनुबंधन किया

यह कंपनी राज्य सरकार को प्रदेश की वित्तीय स्थिति को स्वस्थ व चुस्त बनाने में मदद करेगी

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जून। कर्नाटक सरकार द्वारा अमेरिका की एक कन्सल्टिंग फर्म को हायर करने को लेकर एक तीखी बहस छिड़ गई है। दरअसल, कर्नाटक सरकार कांग्रेस की गारंटियों को लागू करने के बाद अस्त व्यस्त हुई अपनी वित्तीय स्थिति का चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए इस फर्म की मदद ले रही है, लेकिन विपक्षी भाजपा का मानना है कि "विदेशी फर्म की मदद लेना शासन की बागडोर ईस्ट इण्डिया कंपनी को सौंपने के समान है।"

कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाय. विजेन्द्र ने राज्य सरकार के इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए उसे "अनैतिक एवं चौंका देने वाला" बताया। विजेन्द्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "एक्स" पर लिखी एक पोस्ट में कहा कि "कर्नाटक की कांग्रेस सरकार स्वयं को प्रभावी ढंग से अनुपयुक्त एवं अक्षम घोषित कर रही है। जब राज्य सरकार किसी विदेशी एजेंसी के दिशा निर्देशों से संचालित होती है, तब लोक कल्याण की भावना गौण हो जाती है और निर्दोष नागरिक ही पीड़ा भुगतते हैं।"

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुण्डूराव ने राज्य सरकार के निर्णय की तरफदारी करते हुए कहा कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी कन्सल्टिंग फर्म के अलावा मैकिन्से, के.पी.एम.जी. तथा डैलॉइट आदि विदेशी फर्मों की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कर्नाटक के भाजपाध्यक्ष ने इस अनुबंधन को "ईस्ट इंडिया कंपनी" की वापसी की संज्ञा दी।
- भाजपा ने यह भी कहा कि, जब भी विदेशी कंपनी, कब और कैसे और कितने टैक्स लगाने की सलाह देती है, प्रदेश के मध्यम वर्ग व कमज़ोर वर्ग को सबसे ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि, सभी वैलफेयर स्कीम्स को रोक देने की पहली सलाह होती है।
- कांग्रेस ने प्रत्युत्तर में कहा कि, प्र.मंत्री मोदी ने भी अपना "2047 विज़न डॉक्युमैंट" तैयार करने के लिये, इसी अमेरिकी कंपनी को जिम्मेवारी सौंपी थीं। इसके अलावा, प्र.मंत्री मोदी समय-समय पर अन्य विदेशी कन्सल्टिंग कंपनियों, मैकिन्सी, के.पी.एम.जी., डलॉइट की सलाह लेते रहे हैं।

नीट पी.जी. प्रवेश परीक्षा टली

नई दिल्ली, 22 जून। केंद्र सरकार ने उच्च चिकित्सा शिक्षा एम.बी.बी.एस. पूरा करने के बाद पी.जी. में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट पी.जी. एंट्रेस एग्ज़ाम टालने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की नीट पीजी परीक्षा टाल दी गई है। परीक्षा की नयी तिथियां की घोषणा बाद में की जाएगी।

नीट पीजी प्रवेश परीक्षा कल 23 जून को निर्धारित थी। मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही की कुछ प्रवेश परीक्षाओं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- एन.टी.ए. ने नीट पीजी परीक्षा टालने की घोषणा कर दी है। परीक्षा की नयी तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 23 जून को निर्धारित थी।

भजनलाल पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान अपने विधानसभा क्षेत्र से शुरु किया

भजनलाल सरकार का स्पष्ट मैसेज है, "अतिक्रमण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा"

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 22 जून। राजधानी जयपुर में न्यू सांगानेर रोड से वंदे मातरम मार्ग तक प्रस्तावित 100 फीट सेक्टर रोड पर 251 से ज्यादा अतिक्रमण हटाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण पिछले 3 दिनों से अभियान चला रहा है।

भले ही यह कार्रवाई राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है, लेकिन सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सीट है, वे यहीं से पहली बार विधायक चुनाव जीते और मुख्यमंत्री भी बने। इसके बावजूद अतिक्रमियों पर सख्त कार्रवाई में उन्होंने कोई राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होने दिया। माना जा रहा है कि, मुख्यमंत्री ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अतिक्रमियों पर कार्रवाई के जरिए साफ संदेश दिया है कि "जयपुर शहर समेत प्रदेशभर में कहीं भी अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर कोई भी विधानसभा क्षेत्र क्यों न हो।"

जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत तमाम बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण करने की समस्या पिछले काफी सालों से लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी मंत्री-विधायक अपने क्षेत्र में वोट बैंक की वजह से कार्रवाई नहीं होने देता है, और अतिक्रमण की यह समस्या "नासूर" बन गई।

इसका प्रमुख उदाहरण जयपुर परकोटा है, जब वर्ष 2019 में यूनेस्को ने "जयपुर चारदीवारी" विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, तब परकोटे की दीवार से सटे हुए 400 से ज्यादा छोटे-बड़े अतिक्रमण हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन नगर विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इन अतिक्रमणों को हटाने के नाम पर चुप्पी साध ली। क्योंकि जयपुर परकोटे में किशनपोल, हवामहल, आदर्श नगर और सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के मंत्री-विधायक थे, जो किसी भी सूरत में अपने वोट बैंक को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस के इन मंत्री-विधायकों के दबाव में परकोटे से अतिक्रमण हटाने का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि धारीवाल ने जयपुर परकोटे को अतिक्रमण मुक्त करने के बड़े बड़े दावे किए थे, यहां तक कि ड्रोन सर्वे करवाकर चारदीवारी के नज़दीक हो रहे सभी अवैध निर्माणों को चिन्हित करने की बात भी कही थी, लेकिन ये सभी दावे सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गए।

अतिक्रमण बढ़ने का एक दूसरा प्रमुख कारण यह भी था कि, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा की नगरीय निकायों में अपना महापौर बनाने के लिए परिसीमन के नाम पर वार्डों को छोटा करके वोट बैंक को अपने हिसाब से बांटा था, जिसका कांग्रेस को फायदा भी मिला, लेकिन सत्ता की इस चाहत के कारण अवैध निर्माण और अतिक्रमणों पर कोई एक्शन नहीं लिया। जयपुर शहर के दो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जे.डी.ए. प्रशासन ने गत 18 जून से सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रखा है और हीरापथ, बी-2 बाईपास से वंदेमातरम् मार्ग तक 100 फीट सैक्टर रोड सीमा के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं।
- कुल 251 अतिक्रमणों में से 225 कब्जे हटाए जा चुके हैं।
- सरकार की इस कार्यवाही से जयपुर हैरिटेज के उन क्षेत्रों में भी सुगबुगाहट है, जहां लोगों ने परकोटे व अन्य जगहों पर भारी अतिक्रमण कर रखा है।
- ज्ञातव्य है कि, 2019 में जब जयपुर के चार दीवारी क्षेत्र को युनैस्को ने विश्व विरासत घोषित किया था तब परकोटे से सटे 400 छोटे-बड़े अतिक्रमण हटाने की सिफारिश की गई थी, पर तत्कालीन गहलोत सरकार व उनके नगर विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस पर चुप्पी साधे रखी।
- सरकार के ठंडे रूख का कारण था कि, हैरिटेज निगम की चार सीटों पर कांग्रेस विधायक थे और वे अपने वोट बैंक को नाराज़ नहीं करना चाहते थे।

नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को उम्रकैद

जयपुर, 22 जून। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने तथा पीड़िता को अन्य अभियुक्तों को सौंपने और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने का सिलसिला चलाने वाले अभियुक्त हंसराज, पवन कुमार और जीतू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर कुल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जिले की पॉक्सो कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 3.25 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया। अभियुक्तों ने पीड़िता से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल कर अन्य लोगों के पास जाने को मजबूर करने लगे व उससे जेवर व पैसे भी ऐंठ लिये।